CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

दिनांक: 4 अक्टूबर 2023

सरफेसी अधिनियम 2002

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स " और विषय विवरण "सरफेसी अधिनियम, 2002" शामिल हैं। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "अर्थव्यवस्था" अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *सरफेसी अधिनियम 2002 क्या है?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-03: अर्थव्यवस्था*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत विनियमित संस्थाओं (आरई) को निर्देश जारी किए हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की पृष्ठभूमि:

- सरफेसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि बैंक कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी भी उधारकर्ता की संपत्ति को न्यायालय में जाए बग़ैर जब्त किया जा सकता है।
- सरफेसी अधिनियम, 2002 केवल सुरक्षित ऋणों के मामलों में लागू होता है जिस में अंतर्गत बैंक अंतर्निहित प्रतिभूतियों जैसे कि दृष्टिबंधक, बंधक, गिरवी आदि को लागू कर सकते हैं।
- "सुरक्षा हितों" को स्थापित करने और अवैतनिक ऋणों की वसूली के लिए, उन्हें सिविल अदालतों या अन्य नामित न्यायाधिकरणों से निपटना।
- इस खींची गई प्रक्रिया के कारण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया धीमी हो गई, जिससे यह समझाने में भी मदद मिली कि उधारदाताओं के पास अब गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा क्यों है।

अधिनियम का उद्देश्य:

- सरफेसी अधिनियम 2002 का कानून भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बग़ैर उन लोगों की संपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त होता है जो लोग ऋण नहीं चुकाते हैं।
- सरफेसी अधिनियम 2002 के द्वारा नॉन परफार्मिंग असेट की वसूली में बहुत ज़्यादा ही सुधार आ गया है।

क्षेत्र:

- सरफेसी अधिनियम राष्ट्रव्यापी लागू होता है और **इसमें सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं, चाहे वह चल या अचल हो, ऋणदाता के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई हो।**
- सहकारी बैंकों के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता को 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा विस्तारित किया गया था, और वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) 20 लाख रुपये तक के ऋण चूक से जुड़ी स्थितियों में वसूली कार्यवाही शुरू कर सकती हैं।

अधिनियम के तहत प्रक्रिया:

- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के हस्तक्षेप बग़ैर वित्तीय संस्थान या बैंक डिफॉल्टर्स को डिमांड नोटिस जारी कर सकने के लिए स्वतंत्र होता है और आने वाले 60 दिवसों के अंदर ही उन्हें अपना काम पूरा करना होगा।
- चूककर्ता पक्ष ऋणदाता का नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर कानून के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानो को यह भी अधिकार देता है कि वह आर बी आई के तहत किसी भी गिरवी रखी हुई वस्तु या ऋण प्रतिबंध का विक्रय कर सकते हैं।

पुनर्प्राप्ति के तरीके:

सरफेसी अधिनियम वसूली के तीन तरीके प्रदान करता है:

- **प्रतिभूतिकरण**: धन जुटाने के लिए ऋण को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना, जिसमें अक्सर निवेशकों को ऋण पोर्टफोलियो की बिक्री शामिल होती है।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण:** वसूली और मूल्य को अधिकतम करने के लिए व्यथित परिसंपत्तियों का पेशेवर प्रबंधन और पुनर्गठन।
- **अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हितों का प्रवर्तन**: ऋणदाता अदालत की कार्यवाही के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जे में ले सकता है और बेच या प्रबंधित कर सकता है।

अधिनियम से जुड़े मुद्दे:

- **प्रयोज्यता**: अधिनियम असुरक्षित लेनदारों पर लागू नहीं होता है। असुरक्षित ऋणों के लिए, बैंकों को चूक का दीवानी मामला दायर करने के लिए अदालत का रुख करना चाहिए।
- **बैंकों द्वारा दुरुपयोग:** इस बात की आलोचना की जा रही है कि बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कभी-कभी कठोर होते हैं।
- **उधारकर्ताओं की चिंताएं:** कई उधारकर्ताओं को लगता है कि उन्हें बैंक अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा है।
- **प्रावधानों की व्याख्या:** प्रारंभ में, इस बारे में बहुत भ्रम था कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के कुछ प्रावधानों की व्याख्या कैसे की जाए।
- **उधारकर्ताओं के हितों का संरक्षण:** न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 का उद्देश्य कमजोर न हो। साथ ही उधारकर्ताओं के हितों की भी रक्षा की जाती है।
- **संपत्ति का अधिकार:** हालांकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, और वसूली के अधिकार और अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

समाचार के बारे में अधिक:

- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को अब अपनी वेबसाइटों पर उन उधारकर्ताओं के बारे में एक निर्दिष्ट प्रारूप में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, जिनकी सुरक्षित परिसंपत्तियों को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कब्जे में लिया गया है।
- इन आरई में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और अन्य लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं शामिल हैं।
- ऐसे उधारकर्ताओं की पहली सूची परिपत्र तिथि से छह महीने के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए, बाद में मासिक अपडेट किए जाने चाहिए।
- अधिक पारदर्शिता की दिशा में इस उपाय का उद्देश्य हितधारकों और उधारकर्ताओं को उनकी परिसंपत्तियों की स्थिति में दृश्यता प्रदान करना और वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

सूत्र:
आरबीआई ने बैंकों से सरफेसी अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. सरफेसी अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को ऋण चूककर्ताओं से बचाना और खराब ऋणों की वसूली में तेजी लाना है।
2. यह अधिनियम राष्ट्रव्यापी लागू होता है और ऋणदाता के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई सभी संपत्तियों को शामिल करता है।
3. अधिनियम केवल सहकारी बैंकों पर लागू होता है और इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (A)

प्रश्न-02. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम बैंकों को ऋण के खिलाफ प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों का नियंत्रण लेने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उन्हें प्रबंधित या बेचने की अनुमति देता है।
2. अधिनियम धन जुटाने के लिए ऋणों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
3. सरफेसी अधिनियम असुरक्षित लेनदारों पर लागू होता है, और बैंक उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपरोक्त सभी।
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. वित्तीय संस्थाओं की खराब ऋणों की वसूली को बढ़ावा देने के लिए सरफेसी (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के महत्व और प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शीतकालीन कार्य योजना

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना " शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा के सिविल सेवा परीक्षा के "पर्यावरण और पारिस्थितिकी" अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *दिल्ली प्रदूषण के पीछे क्या कारण हैं?*

- *दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना क्या है?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-03: पर्यावरण और पारिस्थितिकी*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में,केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में लगातार उच्च प्रदूषण के स्तर का मुकाबला करना है।

शीतकालीन कार्य योजना की आवश्यकता:

- **वायु गुणवत्ता खराब होना:** दिल्ली सर्दियों के दौरान गंभीर वायु प्रदूषण का अनुभव करती है, मुख्य रूप से पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जो प्रदूषकों का कारण बनती है।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न श्वसन और हृदय रोग होते हैं। लोगों की स्वस्थ की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

पिछले उपाय और कार्य:

- **धूल प्रदूषण नियंत्रण:** पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण मानदंडों को सख्ती से लागू करना।
- **एंटी-स्मॉग गन:** हवा में धूल और कण पदार्थ को दबाने के लिए एंटी-स्मॉग गन की तैनाती।
- **मशीनों से सफाई:** धूल और प्रदूषकों के संचय को कम करने के लिए सड़कों की मशीनीकृत सफाई।
- **प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र: वाहनों** के उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच और लागू करना।
- **वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट:** आनंद विहार और जहांगीरपुरी जैसे उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए दिल्ली में 13 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट पर कार्रवाई और निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

15-सूत्रीय कार्य योजना:

1. 10 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए जाने हैं, जिनमें से2 मिलियन दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जाएंगे।
2. 611 टीमों के साथ कचरा जलाने पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी।
3. "रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ" पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान।
4. आतिशबाजी पर प्रतिबंध।
5. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन।
6. 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान।
7. धूल को नियंत्रित करने के लिए 82 मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनों की तैनाती।
8. निगरानी उद्देश्यों के लिए एक ग्रीन वॉर रूम की स्थापना।
9. प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत।
10. पराली जलाने से रोकने के लिए 5,000 हेक्टेयर खेत पर पूसा बायो-डीकंपोजर का प्रयोग।
11. धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 530 वाटर स्प्रिंकलर की तैनाती।
12. प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करने और अनुमत आयु से अधिक वाहनों के संचालन को रोकने के लिए 385 टीमों का गठन।
13. 90 चिन्हित उच्च यातायात वाली सड़कों के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रचार।
14. वॉर रूम का निर्माण और प्रदूषण हॉटस्पॉट को संबोधित करने के लिए 13 विशेष टीमों की स्थापना।
15. सर्दियों के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर 298 स्मॉग गनों की तैनाती।

अन्य उपाय:

- **दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसे भारत की ईवी राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए 2020 में दिल्ली ईवी नीति शुरू की।**
- **बायो-डीकंपोजर:** भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा ने बायो-डीकंपोजर, एक माइक्रोबियल तरल स्प्रे विकसित किया है। जब धान की पराली पर छिड़काव किया जाता है, तो यह इसे तोड़ देता है, जिससे मिट्टी में आसानी से अवशोषण होता है। इससे किसानों को पराली जलाने से बचने में मदद मिलती है।
- **हानिकारक** पार्टिकुलेट मैटर के प्रसार को कम करने के लिए, सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष पटाखों की बिक्री, भंडारण, उत्पादन और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
- **बदरपुर पावर प्लांट** को बंद करना: दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाके में पुराने और प्रदूषणकारी कोयला आधारित बिजली संयंत्र को दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया है।
- **स्वचालित उत्सर्जन मापन स्टेशन:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अनिवार्य किया है कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक संयंत्र स्वचालित उत्सर्जन माप स्टेशन स्थापित करें। ये स्टेशन प्रदूषण नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सीपीसीबी को वास्तविक समय डेटा प्रदान करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 15 सूत्री शीतकालीन प्रदूषण योजना पेश की दिल्ली समाचार – द इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. निम्नलिखित में से कितने कारक दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं:

1. वाहनों से उत्सर्जन
2. पराली जलाना
3. हवा की तेज गति
4. निर्माण कार्य की धूल

नीचे दिए गए कोड में से सही कोड का चयन करें:

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर: (c)

प्रश्न-02. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पराली जलाने से रोकने के लिए बायो-डीकंपोजर नामक एक माइक्रोबियल तरल स्प्रे तैयार किया है।
2. एंटी-स्मॉग गन तैनात करने से हवा में मौजूद धूल और कण पदार्थ के दमन में सहायता मिलती है।
3. सीएक्यूएम ने अनिवार्य किया है कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक संयंत्र स्वचालित उत्सर्जन माप स्टेशन स्थापित करें।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपर्युक्त सभी।
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर: (A)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण के कारणों और परिणामों पर सरकार द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण करें और प्रदूषण कम करने के लिए अतिरिक्त रणनीतियों का सुझाव दें।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है